



2026:AHC:2163

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43374 सन् 2025

कल्लू @ मुन्ना एवं 2 अन्य

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: राजीव कुमार त्रिपाठी

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री राजीव कुमार त्रिपाठी, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री पुनीत कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकों कल्लू, सुनील लोधी और सन्तोष लोधी की ओर से वाद अपराध संख्या 255 वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश गुण्डा एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3, थाना कोतवाली कालपी, जिला जालौन, में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस प्रकरण में किसी अनुचित उद्देश्य से मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध आपराधिक इतिहास के सात मामलों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। आवेदक संख्या 2 के विरुद्ध आपराधिक इतिहास के चार मामलों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है तथा आवेदक संख्या 3 के विरुद्ध आपराधिक इतिहास के सात मामलों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिराह के सदस्य, नेता या संयोजक नहीं हैं और उन्होंने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (b) में उल्लिखित किसी गिराह की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गतिविधियों में सहायता नहीं की है। आपराधिक मामलों के जमानत आदेशों की प्रतिलिपियाँ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों के न्यायिक प्रक्रिया से भागने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 08.10.2025 से जेल में निरुद्ध हैं, वचन देते हैं कि यदि जमानत दी जाए तो वे उसकी छूट का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में प्रकरणों की भारी लंबितता के कारण विचारण के किसी शीघ्र समाप्ति की संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, किन्तु आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए प्रकरणों के अतिरिक्त आवेदकों के विरुद्ध कोई अन्य प्रकरण नहीं बताया है।

तथ्यों की समग्रता, अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि यह जमानत देने का उपयुक्त प्रकरण है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक, **कल्लू, सुनील लोधी एवं सन्तोष लोधी**, को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियों पर, समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों को प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देंगे।

(iii) आवेदक (i) प्रकरण के प्रारंभ, (ii) आरोप-निर्धारण, और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अन्तर्गत बयान अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर विचार न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र देंगे कि साक्षियों की उपस्थिति में साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर वे कोई स्थगन नहीं माँगेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक विचार न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण तक सीमित है और किसी भी रूप में प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी। विचार न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सम्पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

06 जनवरी, 2026

विनोद

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)